Humilitation of tribal women

1940. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to a report published in 'India Today' of 15th October, 1994 under the heading, "A tribal women beaten, stripped and fined, seeks justice";

(b) if so, what are the facts and details in this regard; and

(c) what steps Government have taken to save the honour and dignity of the tribal women from such humilitation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) to (c) The information is being collected from the State Government of Maharashtra.

विकलांगों के लिए आरक्षण

1941. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में वर्ग "ग" और "घ" पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण के संबंध में कोई स्थायी प्रशासनिक आदेश है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी नियुक्तियों की संख्या क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंकाबालू) : (क) तथा (ख) जी, हां । सरकार के अधीन "ग" तथा "घ" पदों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण के लिए का०ज्ञा० सं० 36035/7/85-स्था० (एससीटी) दिनांक 1 अप्रैल 1986 तथा का०ज्ञा० सं० 36035/8/896 स्था० (एससीटी) दिनांक 20-11-89 के तहत अनुदेश जारी कर दिए गए हैं । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में सरकारी उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में ऐसे ही आदेश जारी कर दिए गए हैं । मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान समूह "ग" तथा "घ" पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

	1992		1993		1994	
	'ग'	'घ'	'ग'	'घ'	'ग'	'घ'
मंत्रालय/विभाग	83	18	37	13	18	3
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	80	98	195	95	150	54

शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1942. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों से कोई बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अभी तक भी बातचीत न करने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंकाबालू) : (क) से (ग) कल्याण मंत्री ने अन्य पिछड़े वर्गों को

शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सहित आरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक 14 जनवरी, 1995 को बुलाई थी। तथापि कुछ राज्यों में आसन्न चुनावों के कारण उस अवसर पर सभी मुद्दों पर विचार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया। इस बैठक में केवल सिविल सेवा परीक्षा 1995 के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को कुछ छूटें देने के सीमित मुद्दे पर ही चर्चा हुई थी। अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सहित पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए बैठक की कोई तारीख कल्याण मंत्री द्वारा निश्चित नहीं की गई है।

Handicapped rehabilitation programmes

1943. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the percentage of posts and appointments for the handicapped and include rehabilitation of the mentally handicapped persons under the purview of the handicapped rehabilitation programmes; and

(b) whether Government also have a scheme for providing self employment opportunities to the handicapped including the mentally retarded/handicapped persons, if so, the details in this regard and whether the programme involved the creation of a National Fund for development of the handicapped?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) No, Sir. There is no proposal to increase the existing percentage of reservation for handicapped in Government jobs.

(b) Government provide many facilities for promoting self-employment opportunities like telephone booths to handicapped persons, loan at differential rate of interest of 4 percent, allotment of Kiosks, vending stalls and booths, petrol pumps, gas dealership, kerosene oil dealership, etc. Under Integrated Rural Development Programme (IRDP) handicapped persons in rural areas are also eligible for self-employment opportunities like poultry, fishery, dairy and other agro-based activities.

Besides, a proposal to set up a National Handicapped Finance and Development Corporation is also under consideration. The main objectives of the Corporation would be to promote economic and developmental activities and self-employment opportunities for the handicapped persons. A token provision of Rs. one crore has been made in th plan budget for the year 1995-96.

(The Deputy Chairman in the Chair)

STATEMENT BY MINISTER

Correcting Answer to Starred Questions 259 answered on 23rd December 1994 regarding probe into skipper scandal.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): Madam, in the statement referred to in reply to Rajya Sabha Starred Question No. 259, answered on 23-12-1994, regarding the probe into Skipper scandal, asked by Shri Viren J. Shah and Shri Pramod Mahajan, in reply to parts (d) to (g) of the question, in lines 19 and 20, for the words—

> "However, the position of arrears of ground rent, *including* interest on delayed payment or ground rent,"

may be read as—

> "However the position of arrears of ground rent, *excluding* interest on delayed payment of ground rent."